International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 14-03-2022, Accepted: 13-04-2022, Published: 28-04-2022
Volume 8, Issue 2, 2022, Page No. 153-155

छत्तीसगढ़ में समावेशी विकासः एक अध्ययन

डॉ. बलभद्र प्रसाद देवांगन
प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, अशोका महाविद्यालय, उम्मेदपुर, सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
समावेशी विकास की अवधारणा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में मंथन का विषय रहा है। समावेशी विकास केवल राष्ट्रिय आय में वृद्धि, गरीबी में कमी तथा रोजगार में वृद्धि से ही संबंधित नहीं है, अपितु समाज के प्रत्येक व्यक्ति, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चो अर्थात हर नागरिक के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई सर्वोन्मुखी विकास नीति से सम्बंधित है। हालांकि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल देते हुए कुछ सहायक योजनाओ का क्रियान्वयन भी किया गया है, फिर भी छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास की दिशा में समस्याये, रूकावटे और चुनौतियाँ भी है। वर्तमान लेख में इन्ही चुनौतियों की जाँच का प्रयास किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एवं जनजातीय विविधताओ को समेटे हुए छत्तीसगढ़ के गठन को 22 वर्ष पूर्ण हो चुके है, अभी भी यदि जनसंख्या की बसाहट को देखे तो छत्तीसगढ़ गाँवो में ही बसता है और स्थानीय लोगो पर ग्रामीण परिवेश एवं समाज का व्यापक असर देखा जा सकता है। यदि समावेशी विकास की बात करे तो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ यथा किसान न्याय योजना, गोधन योजना, नरवा गरुवा घुरवा और बारी योजना के द्वारा ग्रामीण आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया गया है किन्तु शहरी क्षेत्र अधिक तेजी से विकास को बढाने वाले क्षेत्र हो सकते है। समावेशी विकास की प्रक्रिया में शहरो के विकास की धीमी गति, उच्चस्तरीय शिक्षण संस्थाओ और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओ का सर्वथा अभाव, वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं औद्योगिक विकास की कमी राज्य के समावेशी विकास में रूकावट है।

मूलशब्दः छत्तीसगढ़, समावेशी विकास, औद्योगिक विकास, कृशि आधारित उद्योग, रोजगार।

छत्तीसगढ़ का परिचय
भारत के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश से पृथक होकर 1 नवम्बर 2000 को भारतीय संघ के 26 वें राज्य के रूप छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। आरम्भ से ही अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत के कारण और जनजातीय बहुलता के कारण राज्य की एक अलग पहचान है, ''धान का कटोरा'' कहा जाने वाला यह एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ धान की लगभग 1000 किस्मो का उत्पादन किया जाता है। राज्य की 80 प्रतिशत आबादी कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर अपनी आजीविका हेतु निर्भर है। औद्योगिक विकास एवं परिवहन की दृष्टि से केन्द्रीय छत्तीसगढ़ विकसित है, किन्तु उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिण भाग पिछड़ा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण और 44 प्रतिशत भूदृभाग वनों से आच्छादित होने के कारण विकास की अपार सम्भावनाये विद्यमान है।

समावेशी विकास की अवधारणा
''समावेशी विकास मूल रूप से व्यापक विकास, साझा विकास एवं गरीब समर्थक विकास है'' यह माना जाता है कि किसी देश की निर्धनता में जब कमी आती है तब सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास में आम जनता की भागीदारिता में भी क्रमशः वृद्धि होती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ''समावेशी विकास एक वह प्रक्रिया है जो व्यापक लाभ प्रदान करती है, और सभी के लिए अवसरों की समानता को सुनिश्चित करती है। समावेशी विकास को मुख्यतः अवसर, क्षमता, पहुँच और सुरक्षा इन चार बातो के आधार पर सुनिश्चित किया जा सकता है। क्षमता प्राप्त लोगो को विकास के अवसर देने का प्रयास करना, उनके लिए आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुँच को आसान करना और जब वे विकास के उस स्तर को प्राप्त कर ले तो उस स्तर को निरंतर बनाये रखना ही समावेशी विकास कहलाता है।

छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास की आवश्यकता
सतत् और समावेशी विकास और समृद्धि के लिए धन के समान वितरण की आवश्यकता होती है, अतः राज्य के कृषि प्रधान होने और असंगठित क्षेत्र की प्रमुखता के कारण यह एक चुनौती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 6 वां और जनसंख्या की दृष्टि से 16 वां राज्य है। राज्य में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का होना और औद्योगिक एवं शहरी विकास का धीमा होना समावेशी विकास के लिए चुनौती पूर्ण है। 2021 की जनगणना के अनुसार 73 प्रतिशत आबादी अभी भी गाँवो में निवासरत है तथा कुछ ही शहर है जहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएँ है। कुल साक्षरता की स्थिति देखे तो 70 प्रतिशत आबादी साक्षर है, जिनमे उच्च शिक्षित आबादी का भाग कम है।
कृषि प्रधान राज्य होने के बाद भी वैज्ञानिक कृषि विधियों के प्रयोग की कमी है, अभी भी 24 प्रतिशत किसान वैज्ञानिक कृषि विधियों को नहीं अपनाते, किसानो की गरीबी और उधार उन्हें विकास के लाभ लेने से वंचित करती है। कुछ सरकारी योजनाओ जैसे किसान न्याय योजना, गोधन योजना, कृषि विस्तार योजनाओ का प्रयोग किया गया है किन्तु उनका उनका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है। अतएव राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए अनुसन्धान, कौशल विकास, वैज्ञानिक कृषि विधि का विस्तार एवं आय के वितरण की असमानता को दूर करने हेतु राज्य में समावेशी विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास के लक्ष्य

समावेशी विकास की अवधारणा के आधार पर इसके कुछ अंर्तसंबंधित लक्ष्य निर्धारित किये गए है, जिन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैः

1. गरीबी में कमी,
2. रोजगार में वृद्धि,
3. सामाजिक क्षेत्र का व्यापक विकास,
4. मानव विकास सूचकांक में सुधार,
5. सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओ को कम करना,
6. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में सुधार के प्रयास करना।

छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास की समस्यायें

छत्तीसगढ़ जैसे कृषि आधारित राज्य के लिए समावेशी विकास महत्वपूर्ण है, हालाँकि 1661 के बाद आर्थिक सुधारो के अपनाने के कारण देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आये है, निर्यातों का प्रभाव राज्यों की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक पड़ा है, किन्तु अस्थिर वित्तीय बाजारों और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का भी राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा राज्य में गरीबी, रोजगार, कृषि की पारंपरिक विधियों, रुढ़िवादी ग्राम्य समाज एवं क्षेत्रीय विषमताये समावेशी विकास के लिए समस्याएं पैदा करते है। राज्य में 44 प्रतिशत जनसँख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की है जो विकास की धारा से दूर है, इन्हें शिक्षित करना तथा विकास के लिए प्रेरित करना भी समस्या है।

छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास में चुनौतियाँ

राज्य में अविकसित अधोसंरचना परिवहन की समस्या, रुढ़िवादी और पिछड़ी आबादी की अधिकता ने विकास के मार्ग में निरपेक्ष बाधायें डाली है, इसके साथ ही समावेशी विकास के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैः

- गरीबी निवारण।
- कृषि के वैज्ञानिक तरीको का प्रयोग।
- सरकारी योजनाओ का सही क्रियान्वयन होना, ताकि उनका लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुचे अर्थात् भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना।
- आर्थिक क्षेत्र में महिलाओ की सहभागिता बढ़ाना।
- क्षेत्रीय दबावों एवं समाजार्थिक दबावों से मुक्त विकास योजनाओ का जमीनी क्रियान्वयन करना।
- अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रो में रोजगारोन्मुख व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओ की स्थापना तथा उनका सुचारू संचालन करना।

छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास की स्थिति

राज्य में शिक्षा की स्थिति जानने यदि साक्षर जनसँख्या का प्रतिशत देखे तो 2001 के 64 प्रतिशत की तुलना में 2021 में यह 71 प्रतिशत रहा है। स्वास्थ्य सूचकों के हिसाब से डाक्टर रोगी अनुपात 1:17000 है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सूचकांक 100 में से 52.2 है जो मध्यप्रदेश, हरियाणा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश से बेहतर है। इसके बावजूद 5 वर्ष से कम आयु के बच्चो की मृत्यु दर अधिक है। छत्तीसगढ़ उन उभरते राज्यों में से है जहा शुद्ध राज्य घरेलु उत्पाद अखिल भारतीय स्तर से अधिक रहा है, किन्तु आय असमानता अधिक है। मानव विकास सूचकांक का मूल्य छत्तीसगढ़ के लिए 0.613 रहा, अर्थात् पुरे देश में 31 वाँ रैंक प्राप्त था जो माध्यम क्रम का है। कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के जैसी अनेक योजनाये क्रियान्वित की गई है, किन्तु सिचाई सुविधाओ का अभाव और आधुनिक कृषि विधियों का व्यापक उपयोग न होने के कारण वांछित विकास नहीं हो पा रहा।

छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास हेतु सुझाव

- राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना।
- विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाना तथा शहरी मध्यम उद्योगों का विकास करना।
- महिलाओ की आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता को बढ़ाना।
- पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि कृषि के अलावा वैकल्पिक रोजगार अवसरों का सृजन हो।
- असंगठित क्षेत्र में रोजगार अवसरों की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- सभी के लिए सुगम व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं कौशल निर्माण केन्द्रों की स्थापना करना एवं निरंतर संचालन की व्यवस्था करना।
- विकास में शहरो की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए शहरो में सुविधाओ का विस्तार करना एवं इनका उपयोग विपणन केन्द्रों के रूप में करना।
- संसाधनों के विकेंद्रीकृत वितरण की व्यवस्था करना, विकास कार्यों में पंचायतो एवं निगमों की भूमिका बढ़ाना।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों एवं विविधताओ से परिपूर्ण राज्य है जहां समावेशी विकास की अपार सम्भावनाये मौजूद है। राज्य में उपलब्ध स्त्रोतों एवं मानवीय संसाधनों को उपयोग में लाने हेतु कृषि में रोजगार परक प्रयास करने होंगे ताकि गाँवो से पलायन रोका जा सके एवं गाँवो में ही कौशल निर्माण कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार के विकल्पों को बढ़ाना चाहिए

जिससे रोजगार अवसर तो बढ़ेंगे ही, गरीबी में भी कमी आएगी। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रो का विकास पर्यटन उद्योग के लिए सार्थक होगा। उन क्षेत्रो में पहुँच मार्ग, होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु निजी निवेश को आमंत्रित करना तथा स्थानीय लोगो के घरो में पर्यटकों के रुकने हेतु व्यवस्था करवाना, इस हेतु स्थानीय लोगो को प्रेरित करना भी आय का एक अतिरिक्त साधन हो सकता है। उपलब्ध वन संसाधनों का प्रयोग स्थानीय लोगो को आर्थिक आधार पर करने हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर देना साथ ही राज्य में वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण के द्वारा शहरी क्षेत्रो में नए–नए उद्यम अवसरों को ढूँढ़ना सार्थक होगा।

संदर्भ सूची

1. 11वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिपत्र, योजना आयोग, भारत सरकार
2. 12वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिपत्र, योजना आयोग, भारत सरकार
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2020&21 Bahuguna Sunderlal, sustainable development in India-perspective.